असहयोग आंदोलन

कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

e- content

(M.A. तीसरे सेमेस्टर के छात्रों के लिए)

-प्रो0 सौम्य सेनगुप्ता, अध्यक्ष, इतिहास विभाग,
डी.ए.वी. पी.जी. कॉलेज, आज़मगढ़।

असहयोग आंदोलन (Non-Cooperation Movement) की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को Mahatma Gandhi के नेतृत्व में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्ण विरोध करना और स्वराज (स्वशासन) प्राप्त करना था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा और अहम जन-आंदोलन था।

मुख्य कारण

- रॉलेट एक्ट (1919): बिना जाँच के भारतीयों को जेल भेजने वाला काला कानून।
- जलियांवाला बाग हत्याकांड: अमृतसर में बेकसूर लोगों पर अंग्रेजों की गोलीबारी।
- खिलाफत आंदोलन: तुर्की के खलीफा के समर्थन में मुसलमानों का आंदोलन, जिससे हिंदू-मुस्लिम एकता मजबूत हुई।

प्रमुख कार्यक्रम

- बहिष्कार (नकारात्मक कदम): सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों और वस्तुओं का त्याग।
- स्वदेशी (रचनात्मक कदम): खादी का उपयोग, चरखा चलाना, राष्ट्रीय विद्यालयों (जैसे काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया) की स्थापना।
- उपाधियों और सरकारी पदों को वापस करना।

आंदोलन का अंत

5 फरवरी 1922 को गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के चौरी-चौरा में एक हिंसक घटना हुई, जहाँ भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसा से आहत होकर Mahatma Gandhi ने फरवरी 1922 में इस आंदोलन को अचानक वापस ले लिया। [1, 2,

असहयोग आंदोलन के परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति और समाज में क्रांतिकारी बदलाव आए। भले ही यह आंदोलन अपने मुख्य उद्देश्य "स्वराज" को तुरंत हासिल नहीं कर सका, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत महत्वपूर्ण रहे।

प्रमुख परिणाम

- जन-आंदोलन का रूप: पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन महलों और शिक्षित वर्ग से निकलकर किसानों, मजदूरों, महिलाओं और छात्रों तक पहुंचा।
- ब्रिटिश सरकार में भय: अंग्रेजों को पहली बार अहसास हुआ कि वे भारतीयों की सहमति के बिना भारत पर राज नहीं कर सकते।
- स्वदेशी और खादी का विकास: चरखा और खादी भारतीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे।
- राष्ट्रीय शिक्षा की नींव: काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे स्वदेशी शिक्षण संस्थानों का जन्म हुआ।
- कांग्रेस का कायाकल्प: कांग्रेस एक आम जनता की पार्टी बन गई और इसकी पहुंच देश के कोने-कोने तक हो गई।
- हिंदू-मुस्लिम एकता: खिलाफत आंदोलन के जुड़ाव के कारण इस दौरान दोनों समुदायों के बीच अभूतपूर्व एकता देखी गई।
- गांधी जी का नेतृत्व: Mahatma Gandhi भारतीय राजनीति के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित हुए।

असहयोग आंदोलन को अचानक बंद करने के महात्मा गांधी के फैसले से कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता हैरान, निराश और नाराज थे। सुभाष चंद्र बोस ने तो इस फैसले को एक "राष्ट्रीय विपत्ति" (National Calamity) तक कह दिया था।

प्रमुख नेताओं की प्रतिक्रियाएँ

- सुभाष चंद्र बोस: उन्होंने अपनी पुस्तक *The Indian Struggle* में लिखा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था, तब पीछे हटने का आदेश देना एक राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था।
- जवाहरलाल नेहरू: उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वे जेल में यह खबर सुनकर गहरे सदमे में थे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कश्मीर या कन्याकुमारी के किसी गांव ने हिंसा की, तो उसकी सजा पूरे देश को क्यों मिलनी चाहिए।
- मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास: वे गांधी जी के इस फैसले से इतने नाराज हुए कि उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 'स्वराज पार्टी' का गठन कर लिया ताकि वे परिषदों (Councils) में जाकर सरकार का विरोध कर सकें।
- लाला लाजपत राय: उन्होंने जेल से गांधी जी को एक लंबा पत्र लिखकर इस फैसले के प्रति अपना कड़ा विरोध और असंतोष जताया था।

गांधी जी का तर्क

गांधी जी का मानना था कि आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए। चौरी-चौरा की घटना से उन्हें लगा कि देश की जनता अभी अहिंसा के सिद्धांत को पूरी तरह समझ नहीं पाई है और आंदोलन के हिंसक होने पर ब्रिटिश सरकार को इसे कुचलने का बहाना मिल जाता।

1. किसानों की भूमिका (The Peasantry)

ग्रामीण क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन ज़मींदारों और तालुकादारों के शोषण के खिलाफ एक बड़े संघर्ष में बदल गया।

- अवध (उत्तर प्रदेश) का किसान आंदोलन: बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध के किसानों ने भारी लगान, अवैध करों और 'बेगार' (बिना वेतन जबरन काम कराना) के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया।
- तालुकादारों का बहिष्कार: किसानों ने ज़मींदारों को सामाजिक सुविधाओं से वंचित करने के लिए 'नाई-धोबी बंद' का फैसला किया। बाद में, कई जगहों पर ज़मींदारों के घरों और अनाज के गोदामों पर हमले भी हुए।
- गांधीजी के नाम का प्रभाव: किसानों के लिए 'स्वराज' का मतलब था कि अब उन्हें कोई लगान नहीं देना होगा और ज़मीनें गरीबों में बांट दी जाएंगी।

2. आदिवासियों की भूमिका (The Tribal Communities)

आदिवासी क्षेत्रों में यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की दमनकारी वन नीतियों (Forest Laws) के खिलाफ विद्रोह के रूप में उभरा।

- गुडेम पहाड़ियां (आंध्र प्रदेश): यहाँ आदिवासियों ने अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक आक्रामक गुरिल्ला आंदोलन चलाया। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों को जंगलों में मवेशी चराने, फल और लकड़ियां इकट्ठा करने पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी आजीविका छिन गई थी।
- राजू का प्रभाव: अल्लूरी सीताराम राजू गांधीजी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने आदिवासियों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, गांधीजी के अहिंसा के मार्ग के विपरीत, उनका मानना था कि भारत केवल बल प्रयोग से ही आज़ाद हो सकता है। आदिवासियों ने पुलिस थानों पर हमले किए और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा।

3. छात्रों की भूमिका (The Students)

शहरी क्षेत्रों में आंदोलन को गति देने में छात्रों ने सबसे महत्वपूर्ण और शुरुआती भूमिका निभाई।

- सरकारी संस्थानों का बहिष्कार: हज़ारों छात्रों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया।
- शिक्षकों का इस्तीफा: छात्रों के साथ-साथ प्राचार्यों और शिक्षकों ने भी अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया।
- राष्ट्रीय शिक्षा की शुरुआत: ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के बहिष्कार के कारण देश में काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे नए राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई, ताकि छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
- असहयोग आंदोलन में शहरी मध्यम वर्ग और व्यापारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, विशेषकर आंदोलन के शुरुआती दौर में। इन दोनों वर्गों ने आर्थिक मोर्चे पर ब्रिटिश हुकूमत की कमर तोड़ने में सबसे बड़ा योगदान दिया।

शहरी मध्यम वर्ग की भूमिका (The Urban Middle Class)

शहरों में इस आंदोलन की शुरुआत मध्यम वर्ग की भागीदारी के साथ हुई।

- वकीलों द्वारा अदालतों का त्याग: देश के जाने-माने वकीलों जैसे मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास (सी.आर. दास), आसफ अली और बाबू राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी और कानूनी अदालतों का पूरी तरह बहिष्कार किया।
- परिषद चुनावों का बहिष्कार: मध्यम वर्ग के राजनेताओं और मतदाताओं ने प्रांतीय परिषदों (Council Elections) के चुनावों का बहिष्कार किया। हालांकि, मद्रास की 'जस्टिस पार्टी' (जो गैर-ब्राह्मणों की पार्टी थी) ने इसमें भाग लिया, क्योंकि उनका मानना था कि कौंसिल में प्रवेश करके वे कुछ अधिकार पा सकते हैं।
- विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार: मध्यम वर्ग के परिवारों ने विदेशी कपड़े, जूते और अन्य विलासिता के सामानों का इस्तेमाल बंद कर दिया।

2. व्यापारियों और दुकानदारों की भूमिका (The Traders and Merchants)

आर्थिक मोर्चे पर व्यापारियों ने ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया।

- विदेशी व्यापार से इंकार: बहुत से व्यापारियों और सौदागरों ने विदेशी कपड़ों और चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से साफ मना कर दिया।
- शराब की दुकानों की पिकेटिंग: व्यापारियों और आम जनता ने शराब की दुकानों के सामने पिकेटिंग (Picketing) की—यानी दुकानों के रास्तों को ब्लॉक कर दिया ताकि कोई अंदर न जा सके।
- स्वदेशी को बढ़ावा: व्यापारियों द्वारा विदेशी सामान न बेचने के कारण भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघा (Handloom) के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। इससे ब्रिटिश कपड़ा उद्योग (विशेषकर लंकाशायर की मिलों) को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।

3. मध्यम वर्ग और व्यापारियों के इस सामूहिक प्रयास का ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ा:

- आयात में भारी गिरावट: 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। इसकी कीमत 102 करोड़ रुपये से घटकर केवल 57 करोड़ रुपये रह गई।
- विदेशी कपड़ों की होली: शहरों में चौराहों पर विदेशी कपड़ों के बड़े-बड़े ढेर लगाकर उन्हें आग के हवाले किया गया, जिससे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को बड़ा झटका लगा।

4. आंदोलन शहरों में धीमा क्यों पड़ा?

कुछ समय बाद शहरों में मध्यम वर्ग का यह उत्साह थोड़ा धीमा पड़ने लगा, जिसके मुख्य कारण ये थे:

- खादी का महंगा होना: मिलों में बने विदेशी कपड़ों की तुलना में हाथ से बुनी खादी बहुत महंगी थी, जिसे गरीब मध्यम वर्ग लंबे समय तक नहीं खरीद पा रहा था।
- वैकल्पिक संस्थानों की कमी: सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार तो कर दिया गया, लेकिन उनके स्थान पर भारतीय या राष्ट्रीय संस्थान बहुत धीरे-धीरे बन रहे थे। नतीजतन, छात्र, शिक्षक और वकील वापस सरकारी संस्थानों की ओर लौटने लगे।